कानपुर, सोमवार, 1 जून, 2026
वर्ष: 03, अंक: 134, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

साध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड भारतीय जमीन पर किया अतिक्रमण..>Pg12

कार्डियोलॉजी में होगा सफल उपचार..>Pg03

मूल्य: 2 ₹

जून का झटका: महंगाई नियमों का डबल अटैक

नए नियमों से महंगाई और बढ़ने के संकेत, यूपीआई, पैन और बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। आज यानी 1 जून से नए महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई बड़े आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब, घरेलू बजट, बैंकिंग व्यवस्था और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर से लेकर कारों की कीमतों तक में बढ़ोतरी हुई है, वहीं यूपीआई, पैन कार्ड और एटीएम से जुड़े नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। सरकार और कंपनियों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है, लेकिन आम लोगों के लिए यह राहत से ज्यादा अतिरिक्त बोझ लेकर आया है।

- 1 जून 2026 से कई नए आर्थिक नियम लागू हुए।
- 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपये तक महंगा हुआ।
- 5 किलो फ्री ट्रेड सिलेंडर 11 रुपये महंगा हुआ।
- घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत स्थिर रखी गई।
- पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी सरेंडर करना पड़ सकता है।
- मारुति कारें 30 हजार रुपये तक महंगी हुईं।
- हुंडई ने कारों के दाम 12,800 रुपये तक बढ़ाए।
- यूपीआई भुगतान में अब वास्तविक बैंक नाम दिखाई देगा।
- 10 लाख से अधिक वार्षिक कैश निकासी पर पैन जरूरी होगा।
- कई बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क और निकासी नियम बदले।

सबसे बड़ा असर गैस उपभोक्ताओं पर पड़ा है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 42 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी 11 रुपये महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद होटल, ढाबे, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों पर लागत बढ़ने का असर अब आम ग्राहकों तक पहुंचने की संभावना है। सरकार ने एक घर, एक कनेक्शन व्यवस्था को लेकर भी सख्ती शुरू कर दी है। जिन घरों में पीएनजी पाइपलाइन गैस कनेक्शन मौजूद है, वहां अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन रखने पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। नियमों का पालन न करने पर गैस आपूर्ति बंद करने तक की चेतावनी दी गई है।

वाहन क्षेत्र में भी उपभोक्ताओं को झटका लगा है। मारुति सुजुकी ने अपनी कई कारों की कीमतों में 30 हजार रुपये तक की वृद्धि की है। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी विभिन्न मॉडल्स पर 12,800 रुपये तक दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया था। इसका असर खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे थे।

डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई में भी बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब किसी व्यक्ति को भुगतान करते समय मोबाइल नंबर या कस्टम नाम की जगह बैंक खाते में दर्ज वास्तविक नाम दिखाई देगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का मानना है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने की घटनाओं में कमी आएगी। साइबर विशेषज्ञ भी इसे डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं।

आयकर विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। अब 50 हजार रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं रहेगा। वहीं प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में पैन की अनिवार्यता की सीमा बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि सालभर में 10 लाख रुपये से अधिक नकद निकासी करने वालों के लिए पैन देना जरूरी होगा। सरकार का उद्देश्य बड़े कैश लेन-देन पर निगरानी बनाए रखना बताया जा रहा है।

बैंकिंग सेक्टर में भी कई बदलाव लागू हुए हैं। कुछ बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क और मुफ्त कैश निकासी सीमा में बदलाव किया है। इससे बार-बार एटीएम उपयोग करने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स के लिए 15 जून एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख तय की गई है।

रसोई पर असर

कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से होटल, ढाबे और फूड कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। आने वाले दिनों में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

डिजिटल सुरक्षा मजबूत

यूपीआई में असली नाम दिखने की व्यवस्था लागू होने से फर्जी आईडी और गलत ट्रांसफर के मामलों पर रोक लगेगी। साइबर फॉड पर अंकुश लगाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

कार खरीदना महंगा

मारुति और हुंडई जैसी कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाने से मध्यम वर्ग की कार खरीद योजना प्रभावित हो सकती है। ऑटो सेक्टर में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

टैक्स निगरानी तेज

सरकार ने पैन नियमों में कुछ राहत दी है, लेकिन बड़े कैश लेन-देन पर निगरानी पहले की तरह जारी रहेगी। इससे काले धन पर नियंत्रण की कोशिश मजबूत होगी।

बैंकिंग खर्च बढ़ेगा

एटीएम शुल्क और निकासी नियमों में बदलाव का असर उन ग्राहकों पर ज्यादा पड़ेगा जो बार-बार कैश निकालते हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की रणनीति भी इसके पीछे मानी जा रही है।

नालों के पुरानी स्लैबों का होगा निरीक्षण: नगर आयुक्त

मेकराबर्टगंज में सीसामऊ नाले की पुरानी स्लैब ध्वस्त होने के मामले में एक्शन में नगर आयुक्त

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम के जोन-4 अंतर्गत वार्ड-4 ग्वालटोली क्षेत्र में शनिवार को मेकराबर्टगंज ढाल के पास सीसामऊ नाले की पुरानी एवं क्षतिग्रस्त स्लैब का एक हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। घटना आर.के. इंटरप्राइजेज (फोटो कॉपी) की दुकान के सामने हुई, जहां नाले के ऊपर बनी स्लैब का लगभग 3 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा हिस्सा टूटकर गिर गया।नगर निगम के अनुसार यह सीसामऊ नाला बक्समंडी ढाल से मेकराबर्टगंज ढाल और ग्वालटोली होते हुए भैरवघाट टीपिंग प्वाइंट तक जाता है। नाले की कुल लंबाई लगभग 1875 मीटर तथा चौड़ाई करीब 9 मीटर है। नाले के ऊपर वर्ष 1990 के आसपास नगर निगम द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया था। दोनों ओर कुल 55 दुकानें बनी हुई हैं, जो लगभग 96 मीटर लंबी स्लैब पर स्थित हैं।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि संबंधित स्लैब करीब 40 से 50 वर्ष पुरानी थी। समय के साथ सरिया पूरी तरह जंग लगने से कमजोर हो चुकी थी। घटना के समय लगभग 10 से 15 लोग एक साथ खड़े होकर फोटो कॉपी करा रहे थे, जिससे अतिरिक्त भार पड़ने पर स्लैब का हिस्सा टूट गया।

घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारियों और अभियंताओं ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी कराई तथा क्षतिग्रस्त स्लैब को हटाने और सुरक्षा संबंधी कार्य शुरू करा दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय का कहना है कि क्षेत्र की अन्य पुरानी स्लैबों का भी निरीक्षण कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और समय रहते आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा उपाय किए जा सकें।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान

बीएनएसडी शिक्षा निकेतन, बेनाझाबर में जयंती पर हुआ भव्य आयोजन

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सामाजिक समरसता मंच कानपुर विभाग के तत्वावधान में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन, बेनाझाबर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोकमाता के जीवन, संघर्ष और समाज सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।मुख्य वक्ता आशा श्रीवास्तव ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सम्मान तथा समाज निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि आज भी उनके आदर्श समाज को नई दिशा देने में सक्षम हैं।कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. दिव्या तिवारी ने की। उन्होंने लोकमाता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से उनके पदचिह्नों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आरती द्विवेदी ने किया, जबकि अतिथियों का परिचय प्रिया सैनी ने कराया। धन्यवाद ज्ञापन पूनम शुक्ला ने प्रस्तुत किया।

समारोह में प्रांत संघ चालक भवानी भीख, विभाग संघ चालक डॉ. श्याम बाबू गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक नरेंद्र, प्रांत सघन बस्ती प्रमुख धर्मेंद्र, विभाग संयोजक मुकेश सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के जीवन मूल्यों को वर्तमान समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

फर्जी वन दरोगा बनकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

» बिठूर पुलिस ने नकली आईडी, पुलिस जैसी वर्दी और KTM बाइक बरामद की, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कमिश्नरेट की बिठूर पुलिस ने खुद को वन विभाग का दरोगा बताकर लोगों को ठगने वाले शातिर आरोपी अजब सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसा दे रहा था और उनसे धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक, फर्जी वन दरोगा का पहचान पत्र, पुलिस जैसी वर्दी, स्टार, लोगो, बेल्ट और जूते बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को वन विभाग का अधिकारी बताकर एक युवक की चञ्झरू बाइक हड़प ली थी। इसके बाद बाइक वापस करने के नाम पर उससे रुपये की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जांच में यह भी सामने आया कि अजब सिंह के खिलाफ अन्य जिलों में भी फर्जी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने तथा वाहन हड़पने के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी लोगों पर रौब जमाने के लिए पुलिस जैसी वर्दी और नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल करता था। बिठूर पुलिस आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के संबंध में भी जांच कर रही है।

ईपीएस-95 पेंशनरों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर भरी हुंकार

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल की बैठक शनिवार को रावतपुर बस स्टैंड के निकट स्थित सेंट्रल रीजनल कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी की देखरेख एवं मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही सेंट्रल रीजनल कर्मचारी संघ और कानपुर मंडल के संयुक्त प्रयास से निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर भी लगाया गया, जिसमें कुशल चिकित्सकों ने लोगों की आंखों की जांच की।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने कहा कि समिति पिछले कई वर्षों से ईपीएस-95 पेंशनरों की चार सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। उन्होंने न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन, डीए और पति-पत्नी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर तक कई दौर की वार्ताएं होने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जो सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि संगठन को एकजुट रहकर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में संघर्ष जारी रखना होगा। बैठक को राज नारायण द्विवेदी, जय रूप सिंह परिहार, अनूप कुमार कुशवाहा, सुभाष चौबे, अभिनंदन कुमार पांडे समेत कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। अंत में मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की।

कार्डियोलॉजी में जटिल हृदय रोगियों का होगा सफल उपचार

निर्देशक डॉ राकेश वर्मा की अथक मेहनत से बढ़ रहा कार्डियोलॉजी संस्थान

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग एवं कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक शल्य चिकित्सा संस्थान (एलपीएसआईसीवीटीएस), कानपुर में कार्डियोलॉजी विभाग के कैथ लैब में 'आईवीयूएस-गाइडेड कॉम्प्लेक्स परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन (पीसीआई) कार्यशाला' का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश के अग्रणी हृदय रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लेकर जटिल कोरोनरी धमनी रोगों के उपचार में नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में देश के प्रतिष्ठित इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विजय कुमार रेहण ने विशेषज्ञ संकाय के रूप में भाग लिया। उन्होंने जटिल कोरोनरी धमनी रोगों के उपचार एवं प्रबंधन से जुड़े अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए।

कार्यशाला के दौरान ट्रिपल वेसल डिजीज (टीवीडी) से पीड़ित दो मरीजों का आईवीयूएस-गाइडेड कॉम्प्लेक्स पीसीआई के माध्यम से सफल उपचार किया गया। इस उन्नत तकनीक से धमनी में अवरोधों का सटीक मूल्यांकन कर स्टेंट प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को अधिक

➪ एलपीएसआईसीवीटीस में अत्याधुनिक कार्डियोलॉजी कार्यशाला का आयोजन सम्पन्न

प्रभावी बनाया गया, जिससे उपचार की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

महाराजगंज निवासी ज्ञानेश्वर वर्मा तथा कानपुर निवासी अशोक कुमार का सफल उपचार किया गया। ज्ञानेश्वर वर्मा को तीन स्टेंट तथा अशोक कुमार को दो स्टेंट लगाए गए। दोनों मरीजों की स्थिति ऑपरेशन के बाद स्थिर एवं संतोषजनक बताई गई है। कार्यशाला में संस्थान की कार्डियोलॉजी टीम के डॉ. उमेश पाण्डेय, डॉ. एस.के. सिन्हा, डॉ. हिमांशु, डॉ. मुकेश झा एवं डॉ. मोहित सचान सहित डीएम कार्डियोलॉजी प्रशिक्षुओं, नर्सिंग अधिकारियों, कैथ लैब तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने सक्रिय भागीदारी की। संस्थान के निदेशक प्रो. (डॉ.) राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं आधुनिक हृदय चिकित्सा तकनीकों के प्रसार, चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्यकर्मियों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान भविष्य में भी मरीजों को विश्वस्तरीय हृदय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा क्षेत्र में ज्ञानवर्धन के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

गंगा बैराज बना रणक्षेत्र, मछली पकड़ने के विवाद में चली गोली-तलवार

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। गंगा बैराज इलाके में मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। रामपुर गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट के दौरान गोली व तलवारें चलने से इलाके में दहशत फैल गई।

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आकाश निषाद ने शुभम उर्फ माका पर गोली चला दी। गोली लगते ही शुभम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि

➪ रामपुर गांव में खूनी संघर्ष, युवक को गोली मारने का आरोप, इलाके में भारी तनाव

दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर लाठी-डंडे चलाए, वहीं तलवारें लहराने से गांव में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी आकाश निषाद का नाम पहले भी पुलिस टीम पर हमले के मामले में सामने आ चुका है। यही वजह है कि घटना को लेकर पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है। फिलहाल कोहना थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

आईपीएल फाइनल की रात बना मौत का मैदान!

नवाबगंज में कोचिंग संचालक की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। नवाबगंज इलाके में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर संचालक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। ढुक्कर फाइनल देखने की बात कहकर रात में कोचिंग पर रुके संचालक की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। छात्रों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जबकि परिजनों ने हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जताई है।

यशोदा नगर निवासी 47 वर्षीय प्रकाश चंद्र गुप्ता विष्णुपुरी स्थित डाटा एक्सपर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। करीब दस वर्षों से वह इसी कोचिंग की फ्रेंचाइजी संचालित कर रहे थे। रविवार रात उन्होंने छोटे भाई विकास गुप्ता को फोन कर बताया था कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल फाइनल देखकर ही घर लौटेंगे। लेकिन रात बीत गई और वह वापस नहीं पहुंचे। सोमवार सुबह करीब नौ बजे जब छात्र कोचिंग पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। फर्श पर खून फैला था और प्रकाश गुप्ता

➪ कोचिंग में रुके थे मैच देखने, सुबह छात्रों ने देखा खून से लथपथ शव, भाई बोला- लूटपाट कर बेरहमी से मार डाला

का शव पड़ा था। छात्रों ने तुरंत डॉयल-112 पर सूचना दी।

मौके पर पहुंचे भाई विकास गुप्ता ने दावा किया कि हत्या से पहले लूटपाट की गई। उनका कहना है कि ऑफिस का सामान टूटा पड़ा था, शव को घसीटकर अंदर ले जाया गया था और मृतक की चेन, ब्रेसलेट व मोबाइल गायब थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चेहरे और आंखों पर गंभीर चोटों से साफ है कि हमलावरों ने बेरहमी दिखाई।

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की आंख के ऊपर चोट के निशान मिले हैं और मुंह से खून बह रहा था। हालांकि पर्स और घड़ी बरामद हुई है, पर्स में 15 हजार रुपये भी मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम पैनल से कराने और खुलासे के लिए तीन टीमें गठित करने की बात कही है।

दुर्गा मंदिर की जमीन पर कब्जे का खेल

भाजपा नेता समेत कई पर मुकदमा

» केडीए की एफआईआर में फर्जी ट्रस्ट और कूटरचित दस्तावेजों से मंदिर भूमि हड़पने का आरोप

दबौली प्रकरण से भू-माफियाओं, ट्रस्टों और राजनीतिक संरक्षण पर उठे बड़े सवाल

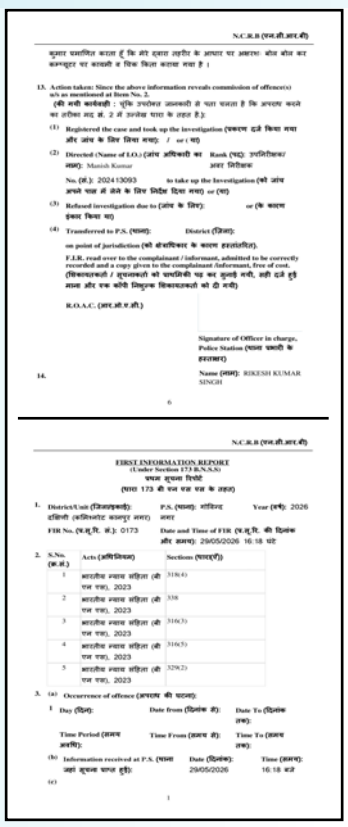

- केडीए की शिकायत के बाद मामला अचानक हाई-प्रोफाइल बन गया।
- जांच में कई दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना गया है।
- कथित ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया अब जांच के घेरे में है।
- राजनीतिक कनेक्शन सामने आने से मामला और संवेदनशील हो गया।
- पुलिस आर्थिक और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।
- मंदिर की जमीन की वर्तमान बाजार कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
- जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि कहीं और संपत्तियों में भी इसी मॉडल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ।

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। दबौली स्थित दुर्गा मंदिर की जमीन को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित ट्रस्ट के जरिए कब्जाने के मामले ने शहर की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में भूचाल ला दिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में भाजपा नेता ललित पाल समेत कई लोगों को नामजद किया गया है। आरोप है कि मंदिर की बहुमूल्य भूमि को सुनियोजित तरीके से हड़पने की साजिश रची गई।

एफआईआर के मुताबिक वर्ष 1984 के सिख दंगों के दोषी रहे दिवंगत पूर्व पार्षद कैलाश पाल के पुत्र ललित पाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक कथित फर्जी ट्रस्ट बनाया। इसी ट्रस्ट के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मंदिर की संपत्ति पर अधिकार जताने की कोशिश की गई। मामले में अमित पाल, गीता पाल, यतीन्द्र सिंह, पंकज शुक्ला और ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। केडीए अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कई दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। जमीन के स्वामित्व, ट्रस्ट गठन की प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन से जुड़े रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराए जाने की भी तैयारी है।मामले के सामने आने के बाद इलाके में भारी चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर और धार्मिक संपत्तियों पर कब्जे के लिए फर्जी ट्रस्टों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है, लेकिन कार्रवाई बहुत कम मामलों में होती है। इस प्रकरण ने प्रशासनिक निगरानी, राजनीतिक संरक्षण और भू-माफियाओं की सक्रियता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कथित ट्रस्ट के जरिए कहीं जमीन की खरीद-फरोख्त या व्यावसायिक उपयोग की तैयारी तो नहीं की जा रही थी। यदि दस्तावेज फर्जी पाए गए तो आरोपियों पर धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई और तेज हो सकती है।

आखिर क्यों अहम है यह मामला?

- मामला धार्मिक संपत्ति से जुड़ा है
- ट्रस्ट के जरिए कब्जे का आरोप बेहद गंभीर
- राजनीतिक नाम सामने आने से बढ़ा दबाव
- प्रशासनिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल

जांच में किन बिंदुओं पर फोकस?

- ट्रस्ट का वास्तविक गठन कब हुआ?
- दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन वैध हैं या नहीं
- जमीन के मूल स्वामित्व का रिकॉर्ड
- क्या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत थी?

कानूनी तौर पर क्या हो सकता है?

- फर्जी दस्तावेज साबित होने पर गिरफ्तारी संभव
- ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है
- जमीन पर कब्जे के दावे खत्म किए जा सकते हैं
- संपत्ति विवाद में राजस्व और न्यायालयी जांच भी बढ़ेगी

जेईई एडवांस्ड 2026 में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के छात्र दिव्यांश कुमार गुप्ता ने लहराया परचम

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के मेधावी छात्र दिव्यांश कुमार गुप्ता ने जेईई (एडवांस्ड) 2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दिव्यांश ने ऑल इंडिया सीआरएल रैंक 1923 प्राप्त कर विद्यालय, परिवार एवं जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

दिव्यांश की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में विद्यालय टॉपर बनने का गौरव भी प्राप्त किया था। लगातार शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

दिव्यांश की सफलता से विद्यालय परिवार में हर्ष और गर्व का माहौल है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उनकी इस उपलब्धि को प्रेरणादायक बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय के प्रधानाचार्य बृजमोहन कुमार सिंह ने दिव्यांश कुमार गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिव्यांश भविष्य में भी अपनी प्रतिभा से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

विद्यालय प्रबंधन एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने दिव्यांश को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

एंडोमेट्रियोसिस के आधुनिक उपचार और मातृत्व संरक्षण पर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसायटी (एफओजीएसआई से संबद्ध) द्वारा तिलक नगर स्थित होटल विजय इंटरनेशनल में ÷एंडोमेट्रियोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट एवं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन रणनीतियाँ÷ विषय पर सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञों ने एंडोमेट्रियोसिस के आधुनिक उपचार तथा महिलाओं की प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।कार्यक्रम का शुभारंभ सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. कल्पना दीक्षित, सचिव डॉ. रेशमा निगम, मुख्य संरक्षक डॉ. मीरा अग्निहोत्री तथा शहर के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।सीएमई की मुख्य वक्ता त्रिची ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. चर्मिला अय्यावू रहीं। उन्होंने ÷रेलुगोलिक्स = एंडोमेट्रियोसिस के मेडिकल मैनेजमेंट के लिए नई ओरल जीएनआरएच एंटागोनिस्ट दवा÷ विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि यह दवा एंडोमेट्रियोसिस से होने वाले दर्द में शीघ्र राहत प्रदान करती है। दिन में एक बार सेवन की सुविधा तथा इंजेक्शन आधारित उपचार की तुलना में कम दुष्प्रभाव इसके प्रमुख लाभ हैं।

डॉ. अय्यावू ने ÷एंडोमेट्रियोसिस में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन÷ विषय पर आयोजित पैनल चर्चा का संचालन भी किया। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने समय पर रोग की पहचान, एएमएच जांच, मेडिकल सप्रेशन, सर्जिकल विकल्पों तथा आईवीएफ के माध्यम से अंडाशय की कार्यक्षमता और प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखने की रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में कानपुर के बड़ी संख्या में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सकीय परामर्शदाताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस के प्रति जागरूकता, समय पर निदान और आधुनिक उपचार पद्धतियों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व संबंधी संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।

सम्पादकीय

प्रभावी-पारदर्शी बीमा कवर अनिवार्य हो

किसी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों के लिए सस्ती व प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। दुनिया के तमाम देशों में सरकारों के स्तर पर ऐसी नीतियां बनी हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संकट आने पर उपचार खर्च के तनाव का रोग अलग से नहीं लेना पड़ता है। विशेषकर बुजुर्ग आबादी का विशेष ख्याल रखा जाता है। जिस उम्र में उनका शरीर क्षीण हो रहा होता है और आय के साधन न के बराबर होते हैं, सरकारी चिकित्सा का सुरक्षा कवच बड़ा संबल होता है। विडंबना यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं गहरे विरोधाभास से जूझ रही हैं। हमारी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खुद बीमार है। देश में कम स्वास्थ्य बजट, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के चलते सरकारी अस्पतालों में सब कुछ होते हुए भी गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को गुणवत्ता का उपचार नहीं मिल पाता है। हाल ही में सामने आए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक नये सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की लगभग आधी आबादी के पास किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा कवर है। लेकिन विडंबना यह है कि स्वास्थ्य बीमा कवर होने के बावजूद उनकी जेब से खर्च होने वाला चिकित्सा व्यय अधिक बना हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं ने बीमा कवरेज के विस्तार को गति दी है। उल्लेखनीय है कि देश के ग्रामीण इलाकों में अब शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बीमा कवरेज अधिक है। इसके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि देश के करोड़ों परिवारों के लिए आज भी बीमार पड़ना गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर देता है। वहीं दूसरी ओर, इस सर्वेक्षण ने एक स्पष्ट खामी को भी उजागर किया है कि आज भी अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक मामले के लिए मरीज के जेब से होने वाले खर्च के औसत बिल 34,000 रुपये से अधिक हैं।यह हकीकत है कि बीमा कवरेज के बाद भी मरीजों के उपचार पर होने वाला खर्च भारत के अधिकांश आम परिवारों की वहन क्षमता से कहीं अधिक है। आखिर देश में बीमा दायरा बढ़ने के बावजूद, मरीजों पर चिकित्सा उपचार का आर्थिक बोझ लगातार क्यों बढ़ रहा है? क्या बीमा कवरेज कारोबार के लिए उत्साहित रहने वाली बीमा कंपनियों और बड़े अस्पतालों की कमाई का ही जरिया बनकर रह गया? हाल के वर्षों में इस अपवित्र गठबंधन के कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन नियामक तंत्र की सख्ती के अभाव में मरीजों के दोहन का यह खेल बदस्तूर जारी है। जानकार बताते हैं कि चिकित्सा उपचार की बढ़ती दर अक्सर मुद्रास्फीति से भी अधिक होती है। निस्संदेह, यह अपवित्र कारोबार मरीजों से मुनाफा कमाने वालों के मानवीय सरोकारों पर सवालिया निशान लगाता है। वैसे चिकित्सा सेवा में मुनाफा बढ़ते देख निजी स्वास्थ्य सेवाओं का दबदबा भी बढ़ा है। हाल के वर्षों में सरकारी अस्पतालों की बदहाली के चलते ज्यादातर भारतीय निजी अस्पतालों की ओर ही रुख कर रहे हैं। लेकिन वहां सरकारी अस्पतालों से कई गुना अधिक उपचार लागत होती है। कोरोना संकट में हमने देखा कि महंगे उपचार के चलते तमाम लोग गरीबी के दलदल में चले गए। दरअसल, आज हालातवश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं वाले अस्पतालों में भर्ती होने की हिस्सेदारी घटने के साथ ही मरीजों को अनिवार्य रूप से अधिक महंगे विकल्पों की ओर धकेला जा रहा है, जिससे बीमा सुरक्षा के लाभ कम हो रहे हैं।

आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन भी एक और बाधा बनी है। वहीं देर से मिलने वाली सरकारी चिकित्सा बीमा राशि भी मरीजों के लिए किफायती सेवाओं को बाधित कर रही है। यदि इन सरकारी योजनाओं में सूचीबद्ध अस्पताल मरीजों के उपचार से पीछे हट जाते हैं तो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित बीमा की अवधारणा खतरे में पड़ जाती है, जिससे वंचित होने से नागरिकों का उपचार अधर में लटक जाएगा। निस्संदेह, बीमा कवरेज ही काफी नहीं है, देश को अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत करना होगा।

साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अस्पताल के बिल मजबूर लोगों की आय व बचत को पलीता लगाते रहेंगे।

सरकारी स्कूलों की आपराधिक उपेक्षा क्यों

यशवंत सचदेवा

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख...

स्कूली शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में 'नीति' आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह विडंबना ही है कि 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली की धूल में नीति-आयोग की यह रिपोर्ट कहीं खो सी गयी है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सिर्फ चौंकाते ही नहीं, परेशान भी करते हैं। जैसे, यह रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी और निजी स्कूलों की स्थितियों का अंतर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बता रहा है कि देश के भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं कितनी खोखली हैं।

प्रधानमंत्री एक से अधिक अवसरों पर अपने भाषणों में इस आशय के दावे कर चुके हैं कि देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मसलन, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि देश में प्रति सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है, हर रोज एक नया कॉलेज खुल रहा है। प्रधानमंत्री आईआईटी और आईआईएम के विस्तार के दावे भी कर चुके हैं। लेकिन नीति-आयोग की यह रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी कमजोरियों को उजागर कर रही है। पिछले एक दशक के विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट बता रही है कि हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकारी और गैर-सरकारी में बांटकर समूची शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिये हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। रिपोर्ट में ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र में हम किस तरह की आपराधिक उपेक्षा बरत रहे हैं। उदाहरण के लिए सन्? 2017 और 2024 के बीच देश में 87000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गये, इसकी तुलना में निजी स्कूलों की जैसे बाढ़-सी आ रही है।यह सही है कि हाल के कुछ सालों में, विशेष कर कोरोना-काल के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है, पर इसका कारण शिक्षा का स्तर नहीं, अभिभावकों की आर्थिक विवशता कहीं अधिक है।

वैसे, यह भी एक विडंबना ही है कि आज देश में हमारी शिक्षा भी गरीब और अमीर में बंट गयी है। मान लिया गया है कि आर्थिक अभावों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की विवशता है कि वे सरकारी स्कूलों में जाएं जहां पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है। आर्थिक स्थिति जरा-सी भी सुधरती है तो यह अभिभावक महंगे स्कूलों की ओर रुख कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का यह बंटवारा हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को 'छोटे-बड़े' का अहसास दिलाने वाली हमारी शिक्षा-नीति एक तरह से शिक्षा के अधिकार के हमारे दावों को ही झुठला रही है।

हम देश के हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार की बात तो करते हैं, पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इस बारे में शायद सोचना ही नहीं चाह रहे। सन्? 2021-22 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10,22,386 सरकारी और 3,35,844 निजी स्कूल हैं। यहां निजी स्कूल का मतलब महंगी पढ़ाई और बेहतर सुविधा है। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि महंगी पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई ही होङ्क हां, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले अभिभावक यह अहसास अवश्य जीते हैं कि उनका स्तर 'ऊंचा' है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बीमार सोच का पालन उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो समता-समानता के दर्शन वाले संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं।'पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया' का नारा देने वाले को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि 'इंडिया' क्या पढ़ रहा है? कैसी पढ़ाई कर रहा है। दुर्भाग्य से यह चिंता कहीं दिखाई नहीं देती। नीति-आयोग की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हमारे स्कूलों की स्थितियों को तो अच्छे ढंग से दिखाया गया है, पर जिस तरह से यह रिपोर्ट अचर्चित ही रही है, वह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए।

आखिर हमें दो तरह की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं देश के हर बच्चे को एक समान और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए? इस बारे में हमारा छोटा-सा पड़ोसी देश नेपाल भी हमें कुछ सिखा सकता है। सुना है नेपाल की नई सरकार ने हाल ही में देश के सारे निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहां यह व्यवस्था की जा रही है कि सारी शिक्षा सरकारी स्कूलों के माध्यम से दी जाये ताकि सब बच्चे एक जैसे स्तर की शिक्षा पा सकें। शिक्षा का अधिकार जितना ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी नहीं है शिक्षा का समुचित अवसर मिलना। शिक्षा को निजी और सरकारी में बांटने का मतलब अवसर की समानता के अधिकार को नकारना है।ज़रूरी है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता संवर्धन का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट पर देश में गहरा और व्यापक चिंतन हो। आज यह सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का अर्थ घटिया शिक्षा पाना ही क्यों माना जाता है? क्यों नहीं हम सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारे बच्चे गर्व से कहें कि वे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूलों में पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, अच्छी साफ-सुथरी कक्षाएं होंङ्क और बच्चों को पढ़ाने वाले सक्षम अध्यापक हों, इन अपेक्षाओं को पूरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों यह नहीं सोचा जाता कि एकल अध्यापक वाले स्कूल में बच्चे उचित शिक्षा कैसे पा सकते हैं?बात शिक्षा के स्तर की होनी चाहिए। हम विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा-प्रणाली वाला देश होने का दावा तो करते हैं, पर हमें इस बात पर शर्म क्यों नहीं आती कि हमारे स्कूलों में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ भी अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ पाता?

बिना रसायन के निष्कर्षण

रिसर्च टीम का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में शोध प्रकाशित

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय की अगुवाई में छह सदस्यीय भारतीय शोध दल को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। रिसर्च टीम का समीक्षा पत्र का प्रकाशन प्रतिष्ठित एल्सेवियर के जर्नल सस्टेनेबल केमिस्ट्री वन वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ है। इस शोध के सह-लेखकों में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के डॉ. अशोक कुमार यादव और नानम रोन्या, तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के डॉ. अमन राठौर, ह्रादेश राजपूत और आयुषी गुप्ता शामिल हैं।

इस शोध में सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन को इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण हरित तकनीकों में से एक बताया गया है, जो औद्योगिक प्रक्रियाओं में जहरीले रासायनिक सॉल्वैंट्स की जगह ले सकती है। जानकारी देते हुए कुलपति प्रो. राय ने कहा, यह शोध केवल एक वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं है, यह उद्योग जगत को एक व्यावहारिक विकल्प देने की कोशिश है जो पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना उत्पादन की गुणवत्ता भी बनाए

रखे।एसएफई तकनीक में कार्बन डाइऑक्साइड को 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान और 73.8 बार दबाव पर एक विशेष अवस्था में लाकर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निष्कर्षण के बाद न तो कोई रासायनिक अवशेष बचता है और न ही अधिक ताप से कीमती यौगिक नष्ट होते हैं।

प्रो. राय ने बताता कि पारंपरिक तरीकों में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वैंट्स न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अंतिम उत्पाद में उनके अवशेष भी रह जाते हैं , एसएफई इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म करती है।÷ इस तकनीक के अनुप्रयोग बेहद व्यापक हैं , चाय और कॉफी का डिकैफिनेशन, आवश्यक तेलों की रिकवरी, समुद्री स्रोतों से ओमेगा-3 फैटी एसिड का पृथक्करण, औषधीय कैनबिनोइड निष्कर्षण और कीटनाशकों व भारी धातुओं से दूषित मिट्टी का पर्यावरण-अनुकूल उपचार इसमें शामिल हैं।

प्रो राय ने आगे बताता कि इस शोध की खास बात यह है कि यह केवल मौजूदा तकनीक का आकलन नहीं करता, बल्कि उद्योग जगत के लिए एक भविष्योन्मुखी रोडमैप भी सामने रखता है।

प्रो. राय ने कहा, ÷यह तकनीक भारत जैसे विशाल कृषि विविधता वाले देश के लिए विशेष रूप से आशाजनक है। बिहार और गंगा के मैदानी इलाकों में एसएफई अपनाने से कृषि उत्पादों को उच्च मूल्य मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनेगी और हरित विनिर्माण में कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह शोध पत्र वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत के कृषि और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय हरित मानकों के अनुरूप ढालने के लिए एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

कुलपति प्रो. राय के प्रेरणादायी सतत् अकादमिक उपलब्धियों पर प्रो बीएस राय, प्रो कनुप्रिया, प्रो राजीव कुमार, प्रो टीके डे, डॉ शर्तेंदु शेखर, डॉ नवीन कुमार सहित अन्य ने शुभकामनाएं दी।

कहाँ दिन गुज़ारा, कहाँ रात की...

नज़्म लिखने वाले अब यादों में

❍ मकनपुर की यादों में ज़िंदा रहेंगे बशीर बद्र

❍ मरहूम अदीब मकनपुरी को बेहद चाहते थे बशीर बद्र

❍ मकनपुर के नाम पर नहीं लेते थे अपनी फीस

स्मृति शेष

हशम नक़वी/ स्वराज इंडिया

मकनपुर/बिल्हौर (कानपुर)। उर्दू अदब के अज़ीम शायर बशीर बद्र के इंतकाल की खबर जैसे ही मकनपुर पहुँची, साहित्य और मुशायरों से जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। मकनपुर के ऐतिहासिक ऑल इंडिया मुशायरे और बशीर बद्र का रिश्ता दशकों पुराना था। यही वजह है कि उनकी विदाई को यहां के लोग अपना निजी नुकसान मान रहे हैं।

मकनपुर ग्राम प्रधान मज़ाहिर हुसैन जाफरी बताते हैं कि उनके पिता ताहिर हुसैन के दौर में बसंत मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले ऑल इंडिया मुशायरे में देश के बड़े-बड़े शायर शिरकत करते थे। उन्हीं के निमंत्रण पर बशीर बद्र भी कई बार मकनपुर आए। उनके साथ बेकल उत्साही, वसीम बरेलवी और अन्य नामचीन शायरों ने भी मंच साझा किया। मकनपुर के बुजुर्ग आज भी उन रातों को याद करते हैं, जब बशीर बद्र अपने सादगी भरे अंदाज़ में मंच पर आते और कुछ ही मिनटों में पूरे पंडाल को अपने अशआर के जादू में बाँध लेते थे।

उनकी शायरी में न बनावट थी, न दिखावा। यही वजह थी कि आम श्रोता भी उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता था। मज़ाहिर हुसैन जाफरी बताते हैं कि बशीर बद्र की एक ग़ज़ल उस दौर में मकनपुर के लोगों की जुबान पर रहती थी। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की ज़मीने,जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा।

वह कहते हैं कि बशीर बद्र सिर्फ बड़े शायर नहीं थे, बल्कि बेहद शांत, विनम्र और रिश्तों को निभाने वाले इंसान भी थे। मुशायरे खत्म होने के बाद भी वह लोगों से घुल-मिलकर बातचीत करते और स्थानीय शायरों की हौसला-अफज़ाई करते थे।और दरगाह पर हाजरी भी देते थे। हजरत मदार से बशीर बद्र को बेहद अकीदत थी उन्होंने एक चर्चा के दौरान खुद कहा था कि मेरा दिल अमरोहा और मकनपुर में बहुत लगता है यहां की फिजाएं सूफियाना हैं और यहां का माहौल अदब की दुनिया के लिए मिसाल है एक छोटे से बच्चे से बशीर ने गजल सुनी तो बरबस कह उठे कि मकनपुर दो चीजें बहुत खास हैं एक यहां वालों की आवाजें और दूसरा शेरी अदब का सलीका।

सन 98 में हुए एक मुशायरे की फाइल फोटो

शायर बशीर बद्र

शायरी के आफताब को लग गया ग्रहण

प्रख्यात शायरा शबीना अदीब का कहना है कि उन्होंने बशीर बद्र को बतौर सामइन सुना। ये शबीना अदीब की शायरी का पहला दौर था, उनका कहना है कि बशीर साहब का जाना सुखन की दुनिया का बड़ा नुकसान है। वो बेहद मुहज्जब और सादा तबियत इंसान थे। शबीना अदीब बताती हैं कि 1987 के आसपास वो मकनपुर मेले के ऑल इंडिया मुशायरे में थी और बशीर साहब ने अपने कलाम से समा बांध दिया था वो उस्ताद शायर अदीब मकनपुरी को पूरी शिद्दत से चाहते थे। वो याद करते हुए बताती हैं कि वो मंजर भोपाली के घर दावत में भोपाल पहुंची तो बशीर साहब को इसकी खबर लग गई और वो मंजर भोपाली के घर आ पहुंचे। वो अपने अशआर की तरह हर दिल में उतर जाते थे। वे रिश्ते निभाने में माहिर थे। अदब की दुनिया में आम आदमी के तासुरात पेश करने वाले बशीर बद्र भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए लेकिन जब जब तितली नाचेगी,हवा चलेगी,एहसास अंगड़ाई लेंगे तब तब बशीर बद्र याद किए जाएंगे।

हर पीढ़ी के शायर थे बशीर बद्र

वरिष्ठ पत्रकार एवं शायर नाजिम नकवी कहते हैं कि बशीर बद्र उन चार शायरों में से एक थे जिन्हें शायरी का स्तंभ माना जाता है।

शहरयार,निदा फ़ाज़ली,मुहम्मद अल्वी के साथ बशीर बद्र को हर पीढ़ी का शायर माना जाता है। बशीर की शायरी की खासियत थी कि उन्होंने सुखन को माशूक की बांहों तक नहीं रहने दिया बल्कि एक ऐसे माशूक की कल्पना की जो जुदाई से डरता नहीं। विरह के गीत नहीं गाता बल्कि जुदाई को इश्क का हिस्सा मानता है। बशीर ने शायरी को पेशा नहीं बनाया। अपने फन को बेचा नहीं। वो दिखावे से दूर सूफियाना जिंदगी जीते थे। यही वजह है कि सूखन के फलक पर चमकने वाले बशीर बद्र ने अपने आखिरी दिन अकेलेपन में गुजारे और इस अजीम शायर के जनाजे में चंद लोग ही इकट्ठा हो सके। बशीर जिंदगी भर एक वतन तलाश करते रहे लेकिन किसी भी शहर को अपना मानकर वहीं के नहीं हुए। उनका सफर भोपाल में खत्म हो गया। उनका जाना अदब की दुनिया में ऐसा है कि जैसे जिस्म से जान जुदा हो जाए। बशीर अपनी सादा तबियत और विस्तृत सोच के लिए हमेशा याद किए जाएंगे।

..तो दस साल में कैसे पात्र से अपात्र हो गया कठेरिया परिवार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। चौबेपुर ब्लॉक के गोगूमऊ गांव निवासी मजदूर सुनील कठेरिया के परिवार को आवास योजना से वंचित किए जाने का मामला अब और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। वर्ष 2016 की आईजीआरएस जांच में जिस परिवार को कच्चे मकान के आधार पर आवास के लिए पात्र बताते हुए संस्तुति की गई थी, उसी परिवार को वर्ष 2026 की जांच में अपात्र घोषित कर दिया गया। दोनों सरकारी रिपोर्टों के बीच सामने आए विरोधाभास ने पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आईजीआरएस शिकायत संख्या 030084816002398 पर 6 सितंबर 2016 को दर्ज निस्तारण आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता सुनील पुत्र रामगोपाल का आवास कच्चा है तथा वह आवास योजना के लिए पात्र हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उनका नाम स्थायी पात्रता सूची में शामिल नहीं है, इसलिए ग्राम सभा की खुली बैठक में नाम सम्मिलित कर पात्रता सूची में दर्ज किया जाए। उस समय जांच अधिकारी ने न केवल परिवार को पात्र माना था, बल्कि आवास उपलब्ध कराने की संस्तुति भी की थी। इसके विपरीत,

- **2016 की जांच में कच्चे मकान का हवाला देकर की गई थी आवास की संस्तुति, 2026 में उसी को बताया अपात्र**
- **दो आईजीआरएस जांच रिपोर्टों ने खड़े किए बड़े सवाल, आखिर दस साल में क्या बदल गया?**

आईजीआरएस शिकायत संख्या 30084826000844 पर 29 मई 2026 को हुई जांच में परिवार को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया।

शिकायतकर्ता फूल दुलारी पत्नी सुनील कुमार कठेरिया द्वारा स्वयं को अत्यंत गरीब एवं कच्चे-जर्जर मकान में रहने वाला बताते हुए आवास की मांग की गई थी। जांच के दौरान ग्राम प्रधान और सचिव मौजूद रहे, जबकि शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित नहीं मिलीं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी पुत्री संजना और ससुर रामगोपाल से जानकारी प्राप्त की गई। जांच आख्या में उल्लेख है कि चार भाइयों के बीच हुए बंटवारे में प्रत्येक को एक-एक कमरा मिला था। शिकायतकर्ता के हिस्से में आए कमरे की दीवारों में पक्की ईंटों का प्रयोग पाया गया,

क्या प्रधान से अदावत का खामियाजा भुगत रहा परिवार?

गोगूमऊ गांव में सुनील कठेरिया के परिवार को लेकर एक चर्चा तेजी से फैल रही है। लोगों का कहना है कि गांव की विभिन्न शिकायतों और सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे उठाने के बाद परिवार और ग्राम प्रधान के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसी अदावत का असर तो आवास योजना की पात्रता पर नहीं पड़ा?

जिन्हें मिट्टी से जोड़ा गया है और उन पर छपाई की गई है। इसी आधार पर परिवार को आवास योजना के मानकों के अनुरूप अपात्र माना गया।हालांकि, इसी निष्कर्ष को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यदि केवल दीवारों में पक्की ईंटों का प्रयोग पात्रता का आधार है, तो मकान की समग्र स्थिति और परिवार की आर्थिक दशा का भी आकलन किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि वर्ष 2016 में इसी परिवार को कच्चे आवास में रहने वाला बताकर आवास दिए जाने की संस्तुति की गई थी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि 2016 में परिवार कच्चे और जर्जर मकान के कारण पात्र था, तो 2026 में ऐसा कौन सा बदलाव हुआ कि वही परिवार अचानक अपात्र हो गया। पीड़ित मजदूर

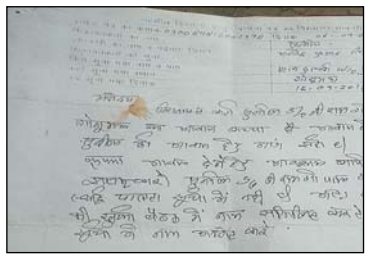

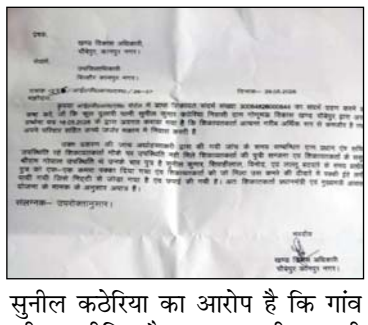

सुनील कठेरिया का आरोप है कि गांव की राजनीति और लगातार की जा रही शिकायतों के कारण परिवार को योजनाओं के लाभ से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।मामले ने अब सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज कर दी है। कई समाजसेवी परिवार के समर्थन में आगे आए हैं। कुछ लोगों ने बच्ची की पढ़ाई में सहयोग और मकान निर्माण में मदद का आश्वासन भी दिया है।

सूर्या हत्याकांड: एनकाउंटर में ढेर असद के घर पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गाजियाबाद। खोड़ा क्षेत्र में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की सनसनीखेज हत्या के बाद अब प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी असद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ असद के मकान पर पहुंची और अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा कर दिया।

गाजियाबाद में छात्र सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन

आरोपी असद के मकान को अवैध कब्जे का बताते हुए ध्वस्तीकरण की तैयारी तेज

बताया गया कि जिस जमीन पर असद का मकान बना है, वह सरकारी भूमि है और उस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया है। एडीएम प्रशासन की ओर से चस्पा किए गए नोटिस में असद के पिता नवाब को 15 दिनों के भीतर एसडीएम कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगा।

प्रशासनिक टीम जब मौके पर पहुंची तो मकान के मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। इसके बाद अधिकारियों ने दरवाजे पर नोटिस चिपका कर कार्रवाई पूरी की। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। उधर, रविवार देर रात पोस्टमॉर्टम के बाद असद के

शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, सुरक्षा कारणों से दफनाने की जगह और समय सार्वजनिक नहीं किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान असद का चाचा मौजूद था।

गौरतलब है कि 28 मई को बकरीद के दिन असद ने मामूली विवाद के बाद छात्र सूर्या चौहान पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में असद को मार गिराया। वहीं, हत्या की साजिश रचने के आरोप में असद के पिता नवाब समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पांच दिन बाद भी खोड़ा इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है।

पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को बड़ी सौगात, मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

» धामपुर में आयोजित विशेष समारोह में मुख्यमंत्री वितरित करेंगे भूमिधरी अधिकार पत्र, वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आज पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 हिन्दू परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। लंबे समय से जमीन के मालिकाना हक की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों को अब भूमिधरी अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे।

बिजनौर जिले के धामपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पात्र परिवारों को अधिकार पत्र वितरित करेंगे।सरकार के इस फैसले से वर्षों से अस्थायी रूप से रह रहे विस्थापित परिवारों को कानूनी पहचान और भूमि पर स्थायी अधिकार मिल सकेगा। प्रशासन के अनुसार भूमिधरी अधिकार मिलने के बाद परिवार अपनी जमीन का वैध रूप से उपयोग, हस्तांतरण और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। कार्यक्रम में करीब 50 पूर्व सैनिकों को भी भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपे जाएंगे। इन पूर्व सैनिकों और विस्थापित परिवारों की यह मांग लंबे समय से लंबित थी।

शासन स्तर पर कई चरणों की प्रक्रिया और सत्यापन के बाद अब इसे अंतिम मंजूरी दी गई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से विस्थापित परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भूमिधरी अधिकार मिलने से बैंक ऋण, आवास, कृषि और अन्य सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। इसके साथ ही जमीन को लेकर भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों की संभावना भी कम होगी। धामपुर में होने वाले समारोह को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

बड़ी संख्या में लाभार्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकार इसे मानवीय संवेदनाओं और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

दिल्ली मंथन के बाद आएगी यूपी भाजपा की नई टीम

» संगठन में बड़े बदलाव तय, कई पुराने चेहरों की छुट्टी और युवाओं को मौका मिलने के संकेत

» स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दिल्ली में चल रही मैराथन बैठकों के बाद जल्द ही नई टीम की घोषणा होने के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के बीच नए नामों को लेकर अंतिम दौर की सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि जून के पहले पखवाड़े में भाजपा प्रदेश संगठन का नया स्वरूप सामने आ सकता है।

2027 चुनाव का ट्रायल मानी जा रही नई टीम

भाजपा नई प्रदेश टीम को सीधे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रही है। इसलिए संगठन में ऐसे चेहरों को तरजीह मिल सकती है जिनकी बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत हो।

युवाओं और सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस

नई टीम में युवा नेताओं के साथ पिछड़ा और दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की तैयारी है। पार्टी सामाजिक संतुलन के जरिए नए वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है।

कई दिग्गजों की भूमिका बदल सकती है

लंबे समय से संगठन में जमे कुछ नेताओं की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। केंद्रीय नेतृत्व प्रदर्शन और सक्रियता के आधार पर नई जिम्मेदारियां तय कर रहा है।

दिल्ली से तय होगा अंतिम फॉर्मूला

प्रदेश संगठन की नई सूची पर अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी। केंद्रीय नेतृत्व इस बार हर नियुक्ति को सीधे चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहा है।

दिल्ली में हुई बैठकों में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ प्रबंधन, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों का दावा है कि इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा और करीब आधे पदों पर नए चेहरों की एंट्री संभव है। कई मोर्चों और प्रकोष्ठों में भी फेरबदल की तैयारी चल रही है।

भाजपा नेतृत्व संगठन को चुनावी मोड में लाने के लिए युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पार्टी का फोकस खासतौर पर पिछड़ा, दलित और युवा वोट बैंक को साधने पर है। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है, जबकि जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में हुई बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक हर बिंदु पर चर्चा हुई। पश्चिम, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्रों को साधने के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि 2027 से पहले संगठन पूरी तरह सक्रिय और चुनावी तैयारी में जुटा दिखाई दे।

फेसबुक पर दोस्ती के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी, शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। साइबर थाना पुलिस ने फेसबुक पर युवती बनकर लोगों को फंसाने वाले अंतरराज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करता था। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए हैं, जबकि पीड़ित के लाखों रुपये फ्रीज कराए गए हैं।मुजफ्फरनगर

प्रतीकात्मक फोटो

साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फेसबुक के जरिए लोगों से दोस्ती कर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले मध्य प्रदेश निवासी शातिर साइबर अपराधी निखिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर गीतिका नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले फेसबुक पर महिलाओं के नाम से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। दोस्ती बढ़ने के बाद वह खुद को निवेश सलाहकार बताकर लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करता था। मोटे मुनाफे और कम समय में रकम दोगुनी होने का लालच देकर वह लोगों से लाखों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लेता था।एक पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया, जिनमें कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में भी साइबर ठगी के मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। वहीं पीड़ित के 24.71 लाख रुपये फ्रीज करा दिए गए हैं, जिससे रकम वापस कराने की प्रक्रिया शुरू हो सके। साइबर थाना पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

विकास भवन पहुंचा युवक

आत्मदाह की चेतावनी से मचा हड़कंप

» विभिन्न कार्यक्रमों में लंच पैकेट का चार साल से भुगतान न मिलने पर क्षुब्ध है युवक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास भवन स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यालय में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक हाथ में बैनर लेकर पहुंचा और भुगतान न होने पर आत्मदाह की चेतावनी देने लगा। युवक का आरोप है कि एनआरएलएम कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराए गए लंच पैकेट का भुगतान पिछले चार वर्षों से लंबित है। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाया और जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

जानकारी के अनुसार, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी गौरव त्रिपाठी मां की रसोई नाम से भोजनालय संचालित करते हैं। गौरव का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में लंच पैकेट उपलब्ध कराए थे, लेकिन संबंधित भुगतान अब तक नहीं किया गया। उनका आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने और भुगतान की मांग उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

लंबे समय से भुगतान न मिलने से परेशान गौरव त्रिपाठी सोमवार को विकास भवन स्थित एनआरएलएम कार्यालय पहुंच गए। हाथ में आत्मदाह की चेतावनी लिखा बैनर देखकर कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें रोकने का प्रयास किया और उच्चाधिकारियों को सूचना दी।

अधिकारी ने दिया आश्वासन

एनआरएलएम के जिला समन्वयक गंगाराम ने बताया कि युवक की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। मामले की जांच कराते हुए नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाएगी। फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन चार वर्षों से भुगतान लंबित होने के आरोप ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित युवक को उसका बकाया भुगतान कब तक मिल पाता है।

सूचना मिलने पर एनआरएलएम के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने

गौरव त्रिपाठी से वार्ता कर उनकी समस्या सुनी और मामले के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया।

आश्वासन मिलने के बाद युवक शांत हुआ और किसी अप्रिय घटना को टाल दिया गया। पीड़ित गौरव त्रिपाठी ने बताया कि चार वर्षों से भुगतान के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसी कारण मजबूर होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

शौर्य प्रशिक्षण में कानपुर देहात का परचम, हिमांशु ने पाया तीसरा स्थान

महोबा में प्रशिक्षण वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हुए सम्मानित, 21 जिलों के बीच बढ़ाया जिले का मान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। महोबा जनपद स्थित विद्या इंटर कॉलेज में आयोजित बजरंग दल के सात दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का सफल समापन हुआ।

प्रशिक्षण वर्ग में 21 जिलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को संगठनात्मक कार्यप्रणाली, नेतृत्व क्षमता विकास, प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद स्थापित करने की कला, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

साथ ही ऊंचाई पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और संकट की स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने के तरीकों की भी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर आयोजित परीक्षा में कानपुर देहात के जिला सहसंयोजक हिमांशु सिंह परिहार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 21 जिलों के प्रतिभागियों

के बीच तृतीय स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से जनपद कानपुर देहात का नाम पूरे क्षेत्र में गौरवान्वित हुआ। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें हिमांशु सिंह परिहार को भी विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापति, क्षेत्रीय संयोजक पुंडेंदु, प्रांत मंत्री राजू पोरवाल, प्रांत संयोजक आचार्य अजीत राज, प्रांत सह संयोजक अमरनाथ, शुभम कौशिक, प्रांत विद्यार्थी प्रमुख नरेश सिंह तोमर, विभाग संगठन मंत्री विकास तथा योगेश सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण वर्ग युवाओं में राष्ट्रसेवा, अनुशासन, साहस, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं।

हर्षोल्लास के साथ मनाई गई राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती

निराला नगर में चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया स्मरण मंदिरों का कायाकल्प कर संस्कृति को किया पुनर्जीवित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद कस्बे के निराला नगर वार्ड में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन, व्यक्तित्व और समाज सेवा के कार्यों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का आयोजन मंडल उपाध्यक्ष विवेक पाल द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत रसूलाबाद के अध्यक्ष देवशरण कमल उपस्थित रहे। अतिथियों ने राजमाता अहिल्याबाई होल्कर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कमलेश चंद्र दिवाकर ने कहा कि राजमाता

अहिल्याबाई होल्कर ने शिक्षा, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए।

उन्होंने देशभर में अनेक मंदिरों, घाटों, पाठशालाओं और धर्मशालाओं का निर्माण एवं पुनर्निर्माण कर भारतीय संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान की। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

नगर पंचायत अध्यक्ष देवशरण कमल ने कहा कि भारतीय वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अहिल्याबाई होल्कर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके आदर्शों और पदचिह्नों पर चलकर ही समाज का समग्र विकास संभव है। कार्यक्रम में देशराज कुशवाहा, बृजेंद्र सविता, राम लखन सविता, राम महेश वर्मा, जीतू त्रिपाठी, रानू मिश्रा, रामआसरे राजपूत, अटल बाजपेई सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राजमाता अहिल्याबाई होल्कर के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ।

अपनी ही सरकार के खिलाफ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी

बाबा साहब की प्रतिमा के आसपास फैली गंदगी और प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में धरना दिया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने अकबरपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर रोशनाई गांव में स्थापित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास फैली गंदगी और प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में यह धरना दिया।

पूर्व सांसद के धरने पर बैठने से जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया और मामला दिनभर चर्चा का विषय बना रहा।

पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने आरोप लगाया कि फतेहपुर रोशनाई गांव में करीब 30 वर्षों से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है, जहां प्रतिवर्ष विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उनका कहना है कि हाल ही में प्रतिमा के निकट एक व्यक्ति को जमीन का पट्टा आवंटित किया गया, जिसके बाद से प्रतिमा स्थल के आसपास लगातार गंदगी डाली जा रही है। इससे न केवल प्रतिमा की गरिमा प्रभावित हो रही है बल्कि स्थानीय लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं।उन्होंने बताया कि गांव के लोग और उनके समर्थक कई बार अपने स्तर से साफ-सफाई कराकर स्थल को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है।

आरोप है कि संबंधित व्यक्ति जानबूझकर प्रतिमा के आसपास गंदगी फैलाता है, इस पूरे मामले को लेकर कई बार तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने एक दिन पूर्व जिलाधिकारी को भी संदेश भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया था और हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

प्रशासन की इस अनदेखी से आहत होकर उन्हें धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर करोड़ों लोगों की आस्था और सम्मान के प्रतीक हैं, ऐसे में उनकी प्रतिमा के आसपास गंदगी फैलाना और शिकायतों पर कार्रवाई न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।धरने के दौरान पूर्व सांसद ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह सांकेतिक

विरोध प्रदर्शन है। यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर समस्या का समाधान नहीं करता है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व सांसद के धरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल बढ़ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम प्रशासन अमित कुमार मौके पर पहुंचे और धरना स्थल पर बैठकर उनकी शिकायत सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धरने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं, पूर्व सांसद के डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने की खबर पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी रही।

अब लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर कब तक इस विवाद का समाधान निकलता है और बाबा साहब की प्रतिमा के आसपास की स्थिति को सामान्य बनाया जाता है।

विद्युत चेकिंग के दौरान अवर अभियंता से अभद्रता, तीन पर मुकदमा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान अवर अभियंता के साथ अभद्रता, सरकारी अभिलेख फाड़ने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। दो नामजद सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।अमरौधा विद्युत केंद्र में तैनात अवर अभियंता रजनीश कुमार द्वारा भोगनीपुर कोतवाली में दी गई तहरीर के अनुसार, 26 मई को वह रैगवां गांव में विद्युत चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान गांव निवासी शिवम दुबे पुत्र अनिल दुबे, आदित्य मिश्रा तथा एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि आरोपितों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए चेकिंग से संबंधित सरकारी कागजात फाड़ दिए। अवर अभियंता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। भोगनीपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिवम दुबे, आदित्य मिश्रा तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा

डीपीआरओ साहब! आखिर कब शुरू होगा आरआरसी सेंटर?

ई-रिक्शा कूड़ा गाड़ी खराब हालत में खड़ी, भवन के मुख्य द्वार पर ताला लटका

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ग्राम पंचायतों में कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लाखों रुपये की लागत से बनाए गए संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र (आरआरसी) कई स्थानों पर केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। इन केंद्रों का संचालन शुरू न होने से एक ओर सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर गांवों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की योजना भी प्रभावित हो रही है।

रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्सी के मजरा गंगादीन निवादा में निर्मित आरआरसी केंद्र इसका जीता-जागता उदाहरण है। यहां कूड़ा प्रबंधन के लिए केंद्र का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। केंद्र परिसर में खरीदी गई ई-रिक्शा कूड़ा गाड़ी खराब हालत में खड़ी है और भवन के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है।ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में आरआरसी केंद्र को संचालित दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता में वहां कोई गतिविधि नहीं हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि यदि केंद्र नियमित रूप से संचालित हो तो कूड़े का उचित निस्तारण संभव हो सकेगा और गांव की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार आएगा।

गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को स्वच्छ एवं कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आरआरसी केंद्रों की स्थापना की गई थी। इन केंद्रों के माध्यम से घरों और सार्वजनिक स्थानों से एकत्रित कूड़े का पृथक्करण और वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण किया जाना था। लेकिन संचालन न होने के कारण योजना का उद्देश्य अधूरा नजर आ रहा है।खेड़ा कुर्सी जैसी बड़ी ग्राम पंचायत में आरआरसी केंद्र बंद पड़े रहने से कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत राज विभाग से केंद्र को जल्द से जल्द चालू कराने और खराब पड़ी ई-रिक्शा को ठीक कराने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव अविनाश शुक्ला ने बताया कि आरआरसी केंद्र काफी समय से बंद है। इसे पुनः संचालित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।लाखों रुपये की लागत से बने आरआरसी केंद्र पर ताला क्यों लटका है? कूड़ा संग्रहण के लिए खरीदी गई ई-रिक्शा खराब हालत में क्यों पड़ी है? यदि केंद्र संचालित नहीं हो रहा है तो उसकी निगरानी और जवाबदेही किसकी है? अब ग्रामीणों की नजरें जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) पर टिकी हैं कि उनके स्तर से क्या कार्रवाई होती है और आखिर यह आरआरसी केंद्र कब शुरू होगा। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों के आश्वासन के बाद आरआरसी केंद्र वास्तव में संचालित होता है या फिर यह मामला केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह जाता है।

कबाड़ बनी खड़ी कूड़ा गाड़ी

दरवाजे पर लगा है ताला

शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में देहात के 9 शिक्षक सम्मानित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह रविवार को अयोध्या स्थित मारवाड़ी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए नवाचारी शिक्षकों ने प्रतिभाग कर अपने-अपने शैक्षिक नवाचारों और अनुभवों को साझा किया।कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी तथा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इसके बाद बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित शिक्षकों और अतिथियों का मन मोह लिया।

एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका पारुल निरंजन ने बताया कि कानपुर देहात से कुल नौ शिक्षकों ने अधिवेशन में प्रतिभाग किया। शैक्षिक क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम के दौरान पारुल निरंजन ने एसोसिएशन के लिए अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत की, जबकि सहायक अध्यापक अंशुल गुप्ता की पीपीटी प्रस्तुति की प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने विशेष सराहना की।

सम्मान समारोह में पारुल निरंजन, शिवनाथ, शैलेश कुमार, अंशुल गुप्ता, विनय कुमार, शब्बीर अहमद, हिमानी गुप्ता, मंजू देवी एवं अपर्णा सिंह को प्रतीक चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।इस उपलब्धि पर खंड शिक्षा अधिकारी अशोक सिंह, एआरपी शोमिल बाबू तथा प्रदीप निरंजन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों द्वारा बच्चों के हित और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे नवाचार सराहनीय हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि जनपद का नाम भी प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित करते हैं।

बंगाल में सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार

बीजेपी के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की नई टीम ने ली शपथ

कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों समेत कई नए चेहरों को मिला मौका, संगठन और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद सोमवार को मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नई टीम के साथ सरकार को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने का संदेश दिया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं और नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति और प्रशासनिक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

कैबिनेट मंत्रियों के रूप में दीपक बर्मन, तपस रॉय, शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और स्वपन दासगुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई।

इन नेताओं को संगठन में लंबे अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में मालती रावा रॉय, राजेश महतो और इंद्रनील खान ने शपथ ली। वहीं राज्य मंत्रियों की सूची में जोएल मुर्मू, हरे कृष्ण बेरा, आनंदमय बर्मन, अशोक डिंडा, नादियार चंद बाउरी, विशाल लामा, शांतनु

प्रमाणिक, मौमिता बिस्वास मिश्रा, उमेश राय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, कौशिक चौधरी, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, अमिया किस्कू, कलिता माझी, गर्गी दास घोष, बिराज बिस्वास, दीपांकर जाना और सुमना सरकार शामिल हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है।

आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिला और युवा चेहरों को शामिल कर पार्टी ने व्यापक प्रतिनिधित्व का संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि नई टीम प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के साथ आगामी चुनावी चुनौतियों की तैयारी में भी अहम भूमिका रही।

आस्था का महासैलाब: 40 दिनों में केदारनाथ पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु

» बाबा केदार के दरबार में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़, यात्रा से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मिला बड़ा सहारा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड स्थित पवित्र केदारनाथ धाम में इस वर्ष आस्था का नया इतिहास बन गया है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के मात्र 40 दिनों के भीतर ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 22 अप्रैल को विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के कपाट खोले गए थे, जिसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भारी आमद बनी हुई है।हर दिन हजारों की संख्या में देश-विदेश से भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रशासन के अनुसार यात्रा के शुरुआती दिनों से ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे और अब यह आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। यात्रा मार्ग पर होटल, धर्मशाला, टेंट, घोड़ा-खच्चर सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा और स्थानीय कारोबारियों की गतिविधियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह मेडिकल कैंप, पुलिस सहायता केंद्र और राहत दल तैनात किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि चारधाम यात्रा में उमड़ रही यह भीड़ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन और स्थानीय व्यापार को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और सुविधाओं में हुए सुधार के चलते इस बार यात्रा सीजन के नए रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है।

क्या स्वराज इंडिया के खुलासे पर लगी मुहर?

40 लाख की कुर्सी का खेल पूरा!

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। दिसंबर 2024 में अमेठी निवासी आशीष सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे एक शिकायती पत्र में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की कुर्सियां कथित तौर पर 40-40 लाख रुपये में बेची जा रही हैं। उस समय इस शिकायत को महज आरोप मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब 31 मई 2026 को जारी तबादला सूची ने एक बार फिर उस पत्र को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

FOLLOW UP

आशीष सिंह की शिकायत के डेढ़ साल बाद सूची के लगभग सभी नाम बने सीएमओ

सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा जिन डॉक्टरों के नाम संभावित सीएमओ के रूप में गिनाए गए थे, उनमें से अधिकांश बाद में विभिन्न जिलों में सीएमओ पद पर नियुक्त होते चले गए।

हालिया सूची में डॉ. सचिन वैश्य और डॉ. रंजन गौतम के नाम शामिल होने के बाद शिकायत में उल्लिखित लगभग पूरी सूची पदस्थापित हो चुकी है।

शिकायत में थे यह नाम

आशीष सिंह की शिकायत में शामिल प्रमुख नाम डॉ. नन्हकू राम, डॉ. नरेंद्र कुमार, डॉ. राजेंद्र कुमार, डॉ. अनिल गुप्ता, डॉ. प्रभा, डॉ. पुष्पेंद्र, डॉ. सचिन वैश्य, डॉ. रंजन गौतम, डॉ. मनोज कुमार शुक्ला, डॉ. अभिषेक, डॉ. दीपा सिंह

संयोग या सिस्टम का सीक्रेट रोडमैप?

यही वह बिंदु है जहां सवाल खड़े होते हैं। आखिर शिकायतकर्ता को पहले से कैसे पता था कि किन-किन डॉक्टरों को आने वाले समय में जिलों की कमान मिलने वाली है? क्या यह महज संयोग था या फिर स्वास्थ्य विभाग के भीतर चल रहे किसी बड़े खेल की पूर्व जानकारी? स्वराज इंडिया ने दिसंबर 2024 में इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब जब सूची के अधिकांश नाम महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच चुके हैं, तो उस समय लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग और तेज हो गई है। सवाल आज भी वही है अगर शिकायत बेबुनियाद थी तो सूची इतनी सटीक कैसे निकली? और अगर शिकायत में दम था तो स्वास्थ्य विभाग में कुर्सियों के इस कथित कारोबार की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

धमकीबाज भीम आर्मी नेता पर दर्ज हुई एफआईआर

» जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी अहम सबूत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। स्वराज इंडिया द्वारा प्रमुखता से उठाए गए मामले के बाद खण्डासा थाना क्षेत्र में कथित दबंगई और धमकीबाजी के आरोपों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना खण्डासा में दर्ज एफआईआर संख्या 0119/2026 ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है।ग्राम सरवनपुर (मौजा अटेसर) निवासी कौशलेन्द्र कुमार ने आरोप लगाया है कि गांव के ही अजीत पासी, जो स्वयं को भीम आर्मी से जुड़ा बताता है, पिछले कई दिनों से उन्हें लगातार धमका रहा था। शिकायत के अनुसार करीब 20 दिन पहले हुए एक गांव के विवाद में विजय कुमार का पक्ष लेने के बाद से ही वह निशाने पर आ गए थे। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने कई बार रास्ते में रोककर हाथ-पैर तोड़ने, जान से मारने और फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। मामला तब और गंभीर हो गया जब 28 मई को कथित रूप से फोन पर गाली-गलौज करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।

FOLLOW UP

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित ने धमकी भरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का दावा किया है, जिसे पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी आधार पर खण्डासा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 एवं 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति को धमकाने का मामला नहीं, बल्कि कानून के भय को चुनौती देने की कोशिश है। अब निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। स्वराज इंडिया लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहा है।

अवैध प्लाटिंग का साम्राज्य: किसके संरक्षण में बिक रही अयोध्या की जमीन?

भू-माफिया मालामाल, खरीदार बेहाल और विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अवैध प्लाटिंग का कारोबार अब चोरी-छिपे नहीं, बल्कि खुलेआम फल-फूल रहा है। सरायरासी, भरतकुंड, सोहावल, रुदौली और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में खेतों को रातों-रात प्लॉट में बदला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि विकास प्राधिकरण की मौजूदगी के बावजूद यह खेल लगातार जारी है। आरोप है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं और अवैध प्लाटिंग करने वालों को पहले से ही ÷सुरक्षा कवच÷ उपलब्ध करा दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक निर्माण की मंजिलों के हिसाब से कथित दरें तय होती हैं और फिर कार्रवाई की फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। खाले का पुरवा क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे कई बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग इसका ताजा उदाहरण बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण भी हुआ, लेकिन कार्रवाई के बजाय मामला ठंडा पड़ गया और प्लॉटों की बिक्री जारी रही। प्रवर्तन विभाग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जरिए क्षेत्र में दबाव और वसूली का नेटवर्क तैयार किया जाता है। जब शिकायतें बढ़ती हैं तो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही जमीन दोबारा बिकने लगती है।

स्थानीय चर्चाओं में अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव, चंदन गुप्ता और प्रशांत दुबे के नाम भी सामने आते हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना बाकी है। सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों का हो रहा है जो जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदते हैं। बाद में

जब जमीन अवैध घोषित होती है तो खरीदार कानूनी और आर्थिक संकट में फंस जाता है। सवाल यह है कि यदि अवैध प्लाटिंग वास्तव में हो रही है तो जिम्मेदार विभाग अब तक इसे रोक क्यों नहीं पाया? यही प्रश्न आज विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ा है।

हाथों में झाड़ू, स्वच्छ अयोध्या का संकल्प

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम द्वारा आयोजित ÷एक रविवार, हर परिवार करे गंदगी पर वार÷ अभियान में रविवार को अयोध्या की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने लता चौक से सरयू तट तक सफाई कर अभियान की शुरुआत की। शहर के 60 वार्डों और करीब 500 स्थानों पर एक साथ चले अभियान में लगभग 50 हजार लोगों ने भागीदारी की।सफाई अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने घरों और मोहल्लों की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ ली। विधायक वेदप्रकाश गुप्ता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों, जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। नगर निगम के अनुसार इस महाअभियान ने अयोध्या में स्वच्छता के प्रति नई चेतना और जनजागरूकता का संचार किया।

अमेरिका-ईरान के बीच 'समझौते' पर संशय गहराया

ट्रंप के दावे के उलट ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी

तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा- ईरानी जहाजों को अब भी होर्मूज से आगे बढ़ने से रोका जा रहा

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरूमध्य को लेकर जारी तनाव कम होने के बजाय और जटिल होता दिखाई दे रहा है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी अभी भी प्रभावी है और ईरानी जहाजों को होर्मूज जलडमरूमध्य से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। यह दावा ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में यह संकेत दे चुके थे कि अमेरिका इस नाकेबंदी को हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार कई ईरानी नाविकों और समुद्री सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी युद्धपोत अब भी ईरानी जहाजों की आवाजाही पर निगरानी रखे हुए हैं। दूसरी ओर व्हाइट हाउस की ओर से यह दावा किया गया था कि यदि ईरान होर्मूज में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगें हटाता है और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है, तो अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकेबंदी में ढील दी जा सकती है।

हालांकि जमीनी हालात ट्रंप के बयानों से मेल खाते नहीं दिख रहे। रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन की रिपोर्टों में भी संकेत मिले हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बन सकी है। अमेरिका अब भी ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम पर कठोर शर्तें मानने और होर्मूज में पूर्ण स्वतंत्र नौवहन की गारंटी मांग रहा है।

क्यों अहम है होर्मूज जलडमरूमध्य?

- दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल परिवहन का रास्ता
- खाड़ी देशों की ऊर्जा आपूर्ति की मुख्य लाइफलाइन
- अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की रणनीतिक मौजूदगी
- वैश्विक तेल कीमतों पर सीधा प्रभाव

ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं?

- नाकेबंदी में ढील देने के संकेत
- ईरान से परमाणु कार्यक्रम सीमित करने की मांग
- होर्मूज को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बनाए रखने पर जोर
- अमेरिकी प्रशासन का दावा- बातचीत जारी

इस बीच अमेरिकी सेंटकॉम ने बीते दिनों ईरान के रडार और ड्रोन नियंत्रण ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। इसके जवाब में ईरान समर्थित बलों की ओर से खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल गतिविधियां बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। इससे वैश्विक तेल बाजारों में चिंता और अस्थिरता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मूज जलडमरूमध्य केवल अमेरिका-ईरान विवाद का केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की धुरी बन चुका है।

दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात इसी मार्ग से गुजरता है और यहां किसी भी सैन्य टकराव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है।

1857 के गुमनाम नायकों को सम्मान दिलाने की मुहिम को मिला जनसमर्थन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इटावा । 1857 की क्रांति के गुमनाम नायकों को इतिहास में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया जनजागरण अभियान व्यापक जनसमर्थन के साथ संपन्न हो गया। एक मई से 31 मई 2026 तक चले इस अभियान में जीता चमार, जंगली-मंगली भंगी और मारून सिंह लोधी जैसे वीर सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। चंबल फाउंडेशन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने 65 गांवों में पहुंचकर लोगों को 1857 की क्रांति के इन उपेक्षित नायकों के योगदान से अवगत कराया।

अभियान के दौरान चौपाल, नुक्कड़ बैठकें, जनसंवाद कार्यक्रम और प्रत्यक्ष संपर्क जैसे माध्यमों से करीब 60 हजार लोगों तक पहुंच बनाई गई। ग्रामीणों को बताया गया कि 1857 की क्रांति केवल कुछ चर्चित नामों तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों के स्थानीय वीरों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों ने इन सेनानियों के इतिहास को पाठ्यक्रमों और सार्वजनिक स्मृतियों में शामिल किए जाने की मांग का समर्थन किया।

इस दौरान चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। लोगों ने कागजी

- एक माह तक चले जनजागरण अभियान में 65 गांवों तक पहुंची चंबल फाउंडेशन की टीम
- 3500 लोगों ने हस्ताक्षर कर इतिहास में सम्मानजनक स्थान देने की उठाई मांग

हस्ताक्षर पत्रों के साथ-साथ 18 मीटर लंबे कपड़े पर भी हस्ताक्षर कर इन वीरों को सम्मान दिलाने की मांग उठाई। अभियान से जुड़े लोगों ने इसे ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

कार्यकर्ताओं ने अभियान के दौरान जीता चमार, जंगली-मंगली भंगी और मारून सिंह लोधी के परिजनों से भी मुलाकात की। उनसे जुड़ी लोककथाओं, पारिवारिक स्मृतियों और ऐतिहासिक जानकारियों को संकलित किया गया, ताकि उनके योगदान का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार किया जा सके।

अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हस्ताक्षर अभियान का दस्तावेज और 18 मीटर लंबा हस्ताक्षरित कपड़ा सौंपा जाएगा। साथ ही मांग की जाएगी कि 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले इन वीर सेनानियों को इतिहास में उनका उचित स्थान दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि गुमनाम नायकों को पहचान दिलाने की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

नेपाल ने भी भारतीय जमीन पर किया अतिक्रमण

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के एक बयान ने भारत-नेपाल संबंधों में नई बहस छेड़ दी है। संसद में सीमा विवाद पर चर्चा के दौरान शाह ने कहा कि 'सिर्फ भारत ने ही नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है।' उनके इस बयान के बाद नेपाल की राजनीति से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक हलचल तेज हो गई।

प्रधानमंत्री शाह ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी और सुस्ता जैसे विवादित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों का समाधान ऐतिहासिक दस्तावेजों, सर्वेक्षण और आपसी बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर भारत को कूटनीतिक नोट भेजा है और दोनों देश विशेषज्ञों की मदद से समाधान खोजने पर सहमत हुए हैं।

शाह के बयान के बाद नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं और पूर्व राजनयिकों ने प्रधानमंत्री से बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग की। कई विशेषज्ञों ने कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र पर आधिकारिक कब्जे का कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है।

विवाद बढ़ने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई जारी करनी पड़ी।

मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय सीमा पार खेती, नो-मैन्स लैंड और सीमांकन से जुड़े स्थानीय विवादों से था, न कि किसी औपचारिक कब्जे से। मंत्रालय ने दोहराया कि नेपाल और भारत 1816 की सुगौली संधि के आधार पर सीमा विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को नया राजनीतिक मोड़ मान रहे हैं।

क्या है लिपुलेख-कालापानी विवाद?: भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है। नेपाल इन क्षेत्रों को अपनी भूमि बताता है, जबकि भारत इन्हें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। यह विवाद 1816 की सुगौली संधि की अलग-अलग व्याख्याओं से जुड़ा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com